the basis of the geological and geophysical work done the drilling is being carried on in many parts of the country at the moment and, therefore, the drilling in Damodar Valley would depend at what priority they put it.

SHRI RAJA KULKARNI : Which are the products in which we have surplus production and which are the products that we are in deficit ? Is the Government making any effort to readjust the product-mix in the refineries so as to have the balance production of all the products ?

SHRI P. C. SETHI : Even for the private sector refineries, Government has acquired the right to fix the product-mix according to the requirements of the country. At present we are importing aviation gasoline, kerosene, furnace oil and lubricants. But the total overall percentage, as has been pointed out in the main body of the answer, of the petroleum products import is only 5.2 per cent.

SHRI S. M. BANERJEE : I am happy that the country is moving towards self-sufficiency. I would like to know the truth about the news item which appeared the day before in a Delhi daily, *The Patriot*, that Government was contemplating taking over of certain foreign oil companies.

SHRI P. C. SETHI : I have already explained this position during the debate on the Grants that as far as taking over of the companies is concerned, there are various alternatives which are being examined by Government at present and unless the examination is complete and we come to certain conclusions, it may not be desirable to say at this stage as to what particular line of action will be taken.

SHRI S. M. BANERJEE : I am not concerned with the procedure they adopt. It is in their mind ? Do they accept it in principle ?

•

MR. SPEAKER ; He has already given the reply,

गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुध कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव

*1203. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ व्यक्तियों ने सरकार को इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि गैर-सरकारी क्षेत्र में आयुध कारखाना लगाने की अनुमति दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मन्त्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी नहीं। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956, के अन्तर्गत हथियार एवं गोले बारूद का निर्माण केन्द्रीय सरकार के एकाधिकार में है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री जी ने जो बतलाया है उसके लिए उनको धन्यवाद। यह खुशी की बात है कि निजी उद्योगपतियों को यह काम नहीं दिया जाने वाला है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि आर्डिनेन्स फैक्ट्रीज में कुछ काम निजी क्षेत्र के लोगों को देने की वजह से काम की कमी हो जाती है ? अगर यह बात सच है तो इस तरह की नीति पर सरकार क्यों चल रही है और इसको बन्द करने के बारे में वह क्या सोच रही है ?

श्री विद्या चरण शुक्ल : सुरक्षा मन्त्रालय की मांगों पर जब बहस हुई थी उस समय मैं ने इस प्रश्न को साफ किया था कि यह धारणा ठीक नहीं है कि जो काम हमने मजबूरन थोड़ा बहुत बाहर वालों को दिया है उसके कारण हमारी आर्डनेंस फैक्ट्रीज के काम में कोई कमी

हुई है। ऐसी बात नहीं है बल्कि उल्टे हमारे काम मे ज्यादा वृद्धि हो उसके लिए हमने छोटी मोटी चीजें जिनका कोई विशेष महत्व नहीं है जोकि निजी क्षेत्र में बन सकती हैं और बनती हैं उनको देने से हम फायदा ही उठाते हैं, कोई नुक्सान नहीं होता है और न इससे हमारी आर्डनेन्स फैक्ट्रीज की उत्पादन क्षमता में कोई कमी ही आती है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह बात सच है कि शरणार्थियों के लिए जो टेंट बनाये जा रहे हैं वह सारे के सारे बाहर से आ रहे हैं जबकि उनको बनाने की क्षमता हमारे देश की फैक्ट्रीज में है...

अध्यक्ष महोदय : आपने आर्मामेंट्स के बारे में पूछा है।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं। क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में कोई एक्स्प्लोजिव फैक्ट्री बन रही है और क्या यह भी सच है कि उसमें निजी उद्योगपतियों को भी काम दिया जाने वाला है ? अगर यह सच है तो ऐसा क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तो क्लियर जवाब दे दिया है। और आप पूछ रहे हैं क्या यह भी सच है, यह भी सच है।

श्री विद्या चरण शुक्ल : मैं समझता हूं आपने टेंट्स से सम्बन्धित प्रश्न को इजाजत नहीं दी है।

उनकी दूसरी बात का मैं जवाब दे रहा हूं कि यह बात सच है कि मध्य प्रदेश में एक एक्स्प्लोजिव फैक्ट्री बन रही है लेकिन यह गलत है कि उसमें किसी तरह का काम प्राइवेट उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। थोड़े बहुत सिविल वर्क्स जो साधारण तौर पर ठेकेदारों से कराये जाते हैं, वैसी बात अलग है बाकी पूरी फैक्टरी हमारे आर्डनेन्स फैक्टरी वाले स्वयं ही बना रहे हैं।

MR. SPEAKER : A supplementary question should not give information and then ask, is it true ? You should ask a direct question.

SHRI JAGANATH RAO : Though armament factories in private sector should not be allowed to manufacture arms and ammunition, should there be any objection if some components which go into the arms and ammunition are allowed to be manufactured by some private firms which have high degree of efficiency ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : There is no objection. Wherever necessary, we do give out various components. But the ultimate manufacture of ammunition and armaments is done only by the ordinance factories and the public sector undertakings and not by private parties.

SHRI M. RAM GOPAL REDDY : I want to know whether the Government has received any offers from private parties to manufacture any armaments and, if so, which are the private parties.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as my knowledge goes, we have received no such offer.

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या यह सही है कि अभी हाल में टैंक-तोड़क गोले बनाने के लिए फरीदाबाद की साइकल पाइप फैक्टरी नाम की फैक्टरी को आर्डर दिया गया है, जिस पर कई केस चल रहे हैं ? उसने एक नये नाम से एक फैक्टरी खोली है और सरकार उसको दो करोड़ रुपये का आर्डर देने जा रही है। उस फैक्टरी के पास न कोई मशीनरी है, न मजदूर है और उसकी पूंजी सिर्फ 200 रुपये है।

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल इससे कैसे पैदा होता है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री महोदय ने कहा है कि किसी गैर सरकारी कारखाने को टैंक-तोड़क गोले आदि किसी तरह के हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी गई है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि इस तरह का आदेश दिया

गया है। मन्त्री महोदय खंडन करें। यह प्रश्न तो बड़ा संगत है।

अध्यक्ष महोदय : अगर पार्टी के लीडर कहते है, तो वह संगत होना ही चाहिए।

श्री विद्या चरण शुक्ल : अभी माननीय सदस्य, श्री जगन्नाथ राव, के प्रश्न के उत्तर में मैंने साफ किया है कि काम्पोनेंट्स इत्यादि हम बाहर वालों को बनाने देते हैं, परन्तु जहां तक शैल या एन्टी-टैंक ग्रिनेड या बम का प्रश्न है, वह केवल हम लोग ही बनाते हैं, किसी प्राईवेट पार्टी को नहीं बनाने देते हैं। यदि हमको बहुत आवश्यकता पड़े, या हम समय पर बनाने में समर्थ न हों, तो हम एम्प्टी आदि जरूर बाहर के लोगों से बनवा सकते हैं। लेकिन उसको बारूद, एक्सप्लासिव, से भरना और उसको पूरा बनाना हमारा काम है। उसके विभिन्न भाग हम बाहर से बनवा सकते हैं। इस बारे में हम आवश्यकता और परिस्थिति के अनुसार निर्णय करते हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि सरकार उस कम्पनी को आर्डर देने जा रही है, जिसके पास न कोई मशीनरी है और जिसने न कोई पूंजी लगाई है और जिसको शुरू करने वाली कम्पनी पर कई केस चल रहे हैं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : इस तरह के बहुत से प्रस्ताव आते रहते हैं। मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य मुझे सूचना दें, तो मैं उनको जवाब दे दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय में कौन बारूद भरता है ?

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आर्थिक विकास के लिए नेपाल को दी गई सहायता

*1206. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने नेपाल को आर्थिक विकास के लिए अब तक कुल कितनी सहायता दी है ; और

(ख) क्या भारत ने वित्तीय सहायता के अतिरिक्त नेपाल को तकनीकी सहायता भी दी है और यदि हां, तो भारत सरकार ने इस बारे में अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI SURENDRA PAL SINGH) : (a) The total amount of aid provided by the Government of India from the beginning of 1951 to the 31st March, 1971 is Rs. 81.52 crores.

(b) Yes, Sir. India has provided technical assistance to Nepal to the extent of Rs. 2.04 crores so far.

श्री मूलचन्द डागा : भारत की ओर से नेपाल को 83 करोड़ रुपये सहायता के रूप में दिये जा चुके हैं। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि हमारे देश से जो शिक्षा-शास्त्री या प्रोफेसर या टेकनीशन नेपाल जाते हैं, वहां उन को कभी भी हैड आफ दि डिपार्टमेंट का पद, या कोई और ऊंचा पद, नहीं दिया गया है, जबकि दूसरे देशों के लोगों को वे पद दिए जाते हैं ; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने क्या कदम उठाया है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : नेपाल से जिस किस्म की मांग आती है, हम उस को पूरा करने की कोशिश करते हैं। खास तौर से जब वहां से टेकनिकल हैंड्ज भेजने के लिए कहा जाता है, तो हम भेजते हैं। मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि उनको किस किस्म का काम या पोजीशन दी जाती है। अगर माननीय सदस्य नोटिस दें, तो मैं इस बारे में इनफर्मेशन दे सकता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा सवाल यह था कि नेपाल को भारत की ओर से 83 करोड़ रुपया सहायता के रूप में दिये जाने के बाद भी हमारे जो प्रोफेसर वहां जाते हैं, उनको कभी